विचार बिन्दु

मासिक वेतन पूरनमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते-घटते लुप्त हो जाता है। –प्रेमचंद

लोग अब पैसे बचाने का नहीं खर्च करने का रुझान रखते हैं

नई आर्थिक नीतियों को अपनाए जाने से पहले भारत एक ऐसा देश रहा है जहां लोगों में बचत की आदत पीढ़ियों से थी। तब भले ही देश की अर्थव्यवस्था के विकास की दर, जिसकी हिन्दू विकास दर कह कर खिल्ली उड़ाई जाती थी, कोई ढाई प्रतिशत के आस पास रहती थी, मगर देश में घरेलू बचत की दर विश्व में सबसे अधिक थी। अब भारतीय रिजर्व बैंक के नये आंकड़ों के मुताबिक़ भारत में शुद्ध घरेलू बचत 47 साल के सबसे निचले स्तर पर है। नये जारी सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2023 में बचत घटकर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.3 प्रतिशत रह गई है जो वर्ष 2022 में 7.3 प्रतिशत थी। भारतीय रिज़र्व बैंक की यह रिपोर्ट आने से पहले ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2022-23 के आंकड़ों ने भी इन रुझानों का संकेत दे दिया था। यह सवाल उठाना स्वाभाविक ही है कि घरेलू बचत में भारी गिरावट का क्या कारण है? आंकड़े बताते हैं कि कुल घरेलू बचत में गिरावट का मुख्य कारण परिवारों की सकल वित्तीय बचत में कमी है। यह सही है कि घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। दैनिक जरूरत की चीजों के दाम, स्कूलों की फीस और इलाज पर खर्च आदि सभी परिवारों पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि ये खर्च परिवार की आय का बड़ा हिस्सा हजम कर जाते हैं। मगर इसके साथ यह भी सच है कि लोग अब मितव्ययता का आदर्श छोड़ते नज़र आते हैं और गैर जरूरी चीजों पर खर्च करते हुए अपनी अंटी को कड़ी नहीं रखते। देश में पिछली सदी के नौवें दशक में खुली अर्थव्यवस्था अपनाई जाने के बाद बाज़ार ने लोगों की बचत की धारणा बदलने का सफल जतन किया है। खुली अर्थव्यवस्था बाज़ार के उभरने अर्थात वहां लोगों द्वारा अधिक से अधिक खर्च करने पर ही परवान चढ़ती है। इसी के चलते रुपये देकर रुपया कमाने वाली बैंकें तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं लोगों को कर्ज लेकर उन्हें अपने सपनों का घर, कारें और अन्य सामान तथा सेवाएं लेने की तरफ आकर्षित करने में लगी रहती हैं। उपभोक्ता बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं में कर्ज देने की होड रहती है। बड़ी संख्या में बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग इसे सौगात मानता है। इसकी ताईद अधिकृत आंकड़े भी करते हैं जो बताते हैं कि इसी अवधि में घरेलू कर्ज के मामले में तेज उछाल आया है। सालाना कर्ज, जीडीपी का 5.8 प्रतिशत हो गया है, जो 1970 के बाद दूसरा उच्चतम स्तर है। स्पष्ट है कि घर और कार आदि के कर्ज का ब्याज चुकाने में आमदनी का बड़ा हिस्सा चला जा रहा है और परिवार के पास बचत के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं। इनके अलावा दूसरे कर्जे भी हैं जिनका चुकारा बचत की संभावनाएं कम करता है। बाज़ार के विश्लेषकों का कहना है कि भारत के बढ़ते घरेलू कर्ज का एक बड़ा हिस्सा 'नॉन मॉर्गेज लोन' हैं। इनमें से आधे से ज्यादा कर्ज कृषि और व्यवसाय से जुड़े हैं। भारत 2022 में 'नॉन मॉर्गेज लोन' के मामले में अमेरिका और चीन सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया और जापान की बराबरी पर आ गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड, शादी और हेल्थ इमरजेंसी के लिए कर्ज अभी कुल घरेलू कर्ज का 20 प्रतिशत से कम है, लेकिन यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बन कर उभर रहा है। पिछले दशक में कर्ज की आसान उपलब्धता ने घरेलू कर्ज को बढ़ाने का काम किया है। भारतीय परिवारों का कर्ज और सेवा का अनुपात यानी 'डेट् सर्विस रेशियो' करीब 12 प्रतिशत है, जो नॉर्डिक देशों जैसा है। ये अनुपात चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से ज्यादा है। इन सभी देशों में घरेलू कर्ज का स्तर ज्यादा है। यह फर्क इसलिए है क्योंकि भारत में कर्ज की दर अब भी ज्यादा और अवधि कम है, जिसकी वजह से अपेक्षाकृत डीएसआर ज्यादा है।

पिछले साल सितंबर में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बचत कम होने और कर्ज बढ़ने की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि लोग कोरोना के बाद कम ब्याज दरों का फायदा उठा रहे हैं और कार, शिक्षा और घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। सरकार में बैठे लोगों का मानना है कि ज्यादा लोग घर और कार जैसी चीजों को खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं, जो किसी संकट का संकेत नहीं है बल्कि यह भविष्य में रोजगार और बढ़ती आय की संभावनाओं से भरा हुआ है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री जी 20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले हमारे देश में कर्ज लेने पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चिंता भी व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि भारत सरकार बुनियादी सेवाओं और सब्सिडी के लिए उधार लेती है, जबकि भारतीय परिवार सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों को खरीदने के लिए लोन ले रहे है। समाजशास्त्री भारत के उपभोक्ता को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा बताते है जहां वह बेहतरीन जिंदगी जीने के सपने देख रहा है, लेकिन उसके पास घटिया सार्वजनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी आय अस्थिर है। पिछले दो वर्षों में परिवारों की सकल वित्तीय बचत में गिरावट इसलिए भी थोड़ी चिंताजनक है क्योंकि गिरावट के साथ-साथ उनकी वित्तीय देनदारियों में भी दो प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि घरेलू बचत कम हो जाने से कॉर्पोरेट निवेश जुटाने के लिए न केवल अतिरिक्त धन का प्रवाह गंभीर रूप से प्रभावित होगा, बल्कि सरकारी उधारी के लिए उपलब्ध संसाधन भी सीमित हो जाएंगे। इसी प्रकार, निवेश पक्ष पर नवीनतम रुझान भी निराशाजनक है। हालांकि 2021-22 में घरेलू निवेश में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई थी, लेकिन 2022-23 में यह फिर से कुछ दशमलव अंकों तक गिरकर 30.2 प्रतिशत हो गया है। बताया जा रहा है कि वास्तव में, यह केवल विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी ही थी जिसने निवेश दरों को बढ़ावा दिये रखा। शेष विश्व से शुद्ध पूंजी प्रवाह पिछले दो वर्षों में लगभग तीन प्रतिशत अंक बढ़कर 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत तक पहुंच गया है। क्षेत्रीय रुझानों से पता चलता है कि कॉर्पोरेट निवेश, जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा निवेशक है, ने अभी तक कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखाया है। कॉर्पोरेट निवेश दरें, जो वास्तव में महामारी के दौरान कॉर्पोरेट बचत दर से भी नीचे गिर कर 2021-22 में जीडीपी के 14.1 प्रतिशत की कॉर्पोरेट बचत दर के बराबर हो गई थीं। यह दर्शाता है कि कॉर्पोरेट जगत ने अतिरिक्त निवेश के लिए संसाधन जुटाने का अपना हौसला खो दिया है। कॉर्पोरेट निवेश एक समय में सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था। निश्चित रूप से, कॉर्पोरेट क्षेत्र में नए निवेश की कमी न केवल संभावित विकास संभावनाओं को प्रभावित करेगी, बल्कि समठा निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए बाहरी कोषों पर हमारी निर्भरता भी बढ़ाएगी। तसल्ली की बात यह है कि सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के मामले में परिदृश्य अपेक्षाकृत बेहतर है, जो अर्थव्यवस्था में कुल निवेश का लगभग दसवां हिस्सा होता है। हालांकि, सरकारी निवेश में लाभ अब भी बजट में उपलब्धियों के किए गए दावों की तुलना में बहुत कम है। नये सांख्यिकी रुझानों से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में सरकार की सामान्य बचत सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत से अधिक कम हो गई है। मगर दूसरी ओर इस अवधि में सरकारी निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 3.9 प्रतिशत से 4.1 प्रतिशत तक मामूली बढ़त भी दर्ज की है। भले ही यह एक दशक का उच्चतम स्तर है, फिर भी कॉर्पोरेट निवेश में मंदी की भरपाई करने के लिए अर्थशास्त्री इसे बहुत कम बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह अधिक निजी निवेश लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

स्पष्ट है कि घर और कार आदि के कर्ज का ब्याज चुकाने में आमदनी का बड़ा हिस्सा चला जा रहा है और परिवार के पास बचत के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं। इनके अलावा दूसरे कर्जे भी हैं जिनका चुकारा बचत की संभावनाएं कम करता है। बाज़ार के विश्लेषकों का कहना है कि भारत के बढ़ते घरेलू कर्ज का एक बड़ा हिस्सा 'नॉन मॉर्गेज लोन' हैं।

इसके अलावा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के आवंटन में आया बदलाव भी कम दिलचस्प नहीं है। नये रुझानों पर निगाह रखने वाले विशेषज्ञ इन रुझानों का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि पिछले दशक के दौरान अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में कुल निवेश की हिस्सेदारी में सापेक्ष गिरावट दर्ज हुई लगती है। इनमें आवास, पानी, बिजली और अन्य सेवाएं, भोजन और गैर-अल्कोहल पेय, कपड़े और जूते, मादक पेय, होटल व रेस्तरां, मनोरंजन और संस्कृति शामिल हैं। दूसरी ओर इस अवधि के दौरान जिन क्षेत्रों में निवेश हिस्सेदारी बढ़ी है उनमें घरेलू उपकरण और साज-सामान, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और परिवहन आदि शामिल हैं। घरेलू बचत में गिरावट और साथ में कर्जों के बोझ से देश के आर्थिक विकास पर कैसा असर रहता है इस पर सबकी निगाह रहेगी। शासन में बैठे अर्थशास्त्रियों तथा नीति निर्माताओं को इन प्रवत्तियों की अंतर्निहित गतिशीलता (डायनेमिक्स) को समझना होगा तथा बाज़ार में मांग को प्रोत्साहित करने तथा वित्तीय स्थिरता के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा क्योंकि इसमें अल्पकालिक मांग की चिंता तथा दीर्घकालीन संरचनात्मक मुद्दे शामिल हैं। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि वित्तीय देनदारियों में वृद्धि के बावजूद, भारत में घरेलू ऋण अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है इसलिए डिफ़ॉल्ट का जोखिम, भारतीय संदर्भ में सीमित माना जाना चाहिए। परिवारों का उधार लेने का मौजूदा उच्च स्तर वित्तीय या व्यापक तौर पर आर्थिक स्थिरता को खतरे में नहीं डालता है, लेकिन अगर ऐसा ही लगातार बना रहता तो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

सत्ता पक्ष व विपक्ष के नारे घनघोर

महावीर सिंह

1. वो संविधान बदलना चाहते है--हम नहीं बदलने देंगे

2. लोकतंत्र मजबूत हाथों में ही सुरक्षित -लोकतंत्र से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे

3. जनता किसको सही समझे??

ज्यों ज्यों लोक सभा के चुनाव आगे बढ़ रहे है, बड़ी रोचक बहस-चर्चाएं गली-मोहलों, चाय-पान की दुकानों और प्रातः सैर के लिए निकलने वाले समूहों में सुनने को मिल रही है। क्या वर्तमान सरकार फिर से प्रचंड बहुमत यानी 400 पार के बहुमत से आई तो संविधान बदल देगी और क्या क्या बदलेगी, कैसे बदलेगी। कुछ राजनीतिक दलों, संगठनों का कहना है कि ऐसा होने नहीं देंगे, कुछ का कहना है ऐसा करके ही मानेंगे। दोनों तरफ के लोग इस बात पर भी बराबर का जोर देते हैं कि--कोई माई का लाल बाबा साहेब के बनाये संविधान को बदल नहीं सकता-- तो दूसरा पक्ष इसी बात को यो कहता है--किसी माई के लाल में इतनी ताकत नही जो बाबा साहेब के बनाये संविधान को बदल दे--!!

घुमन्तु को इन समूहों में बड़े रोचक, अधिकतर सतही पर कुछ सारपूर्ण विचार भी सुनने को मिले जो विद्वान पाठकों के साथ शेयर कर रहा हूँ::--

1. एक समूह के कुछ व्यक्तियों का विचार था कि संविधान बदलना कोई बड़ी बात नहीं। पहले भी 105 बार बदलाव हो चुका है। कोई भी सरकार जिसे संसद में पर्याप्त बहुमत है, पर्याप्त संख्या में राज्य सरकारों का समर्थन है, वह संविधान में संसोधन कर वर्तमानं प्रावधानों को बदल सकती है।

2. किसी ओर ग्रुप में कुछ का विचार था भारत का संविधान चेक व बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित है। संसद/विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के दायित्व व अधिकार परिभाषित है और उन सीमाओं में रह कर ही सही प्रकार से शासन चलाया जा सकता है।

इसके विपरीत कुछ की राय यह थी कि 1975 में यह सब परिभाषाएं धरी रही गई और मनमर्जी से आपातकाल लगा, संविधान में ऐसे संसोधन हुए जिनमें से कुछ को पश्चातवर्ती जनता पार्टी की सरकार नें संसद से निरस्त करवाये।

इसलिए सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि देश का नेतृत्व कैसा है--सब को साथ लेकर चलने वाला है या मन की सुनकर उसी के अनुसार चलने वाला है? इस पर भी निर्भर करता है कि संसद में उस नेता को किस प्रकार के कितने सांसदों का बिना कोई तर्क वितर्क किये समर्थन है?यदि सत्ता पक्ष के व अन्य बहुत से सांसद नेता की सिटी की आवाज पर ही कदमताल करने वाले हों और इतनी संख्या में हों कि विपक्ष को बोलने ही न दें तो क्या नहीं हो सकता है?

3. कुछ अलग राय थी कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज किया जा सकता है। इसलिए ऐसी शंकाएं, केवल, जनता को डराने के लिए है। कुछ की शंकाएं थी कि न्यायपालिका भी तो मैनेज हो सकती। क्या सरकारें 2,4,5 साल में, पर्याप्त संख्या में अपनी विचारधारा के समर्थक न्यायाधीश नियुक्त कर, अपने फैसलों पर अपने पक्ष के निर्णय नही करवा सकती? कई कानून व राजनीति के विद्वान ऐसा कहते रहे है कि यह सम्भव है। जनता को भी, आम चर्चाओं के अनुसार, ऐसा कई बार लगता है।

4. एक व्यक्ति नें कुछ गम्भीर बात कही-- यदि शासन संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुसार और मर्यादाएं से चलता है तों किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं किन्तु हर शासन में, कमोबेश खुल्लमखुल्ला या पर्दे में रह कर मर्यादाएं तोड़ी जाती रही है।

5. किसी एक अन्य समूह में चर्चा के दौरान एक आदमी नें पूछ लिया की वैसे 400 पर सांसद किसी दल के आ भी जाएं तो क्या क्या परिवर्तन कर सकते है?

दूसरे नें कहा--देश के झंडे का रंग बदल सकते है, सेक्युलर व सोसलिस्ट शब्द हटा सकते है, जनगणमन राष्ट्रगान के स्थान पर वन्देमातरम ला सकते है, मंत्रिमण्डलीय शासन प्रणाली की जगह राष्ट्रपति शासन प्रणाली ला सकते है, राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री/मुख्यमंत्री जैसे पद बहुसंख्यकों के लिए आरक्षित कर दें, संसद-विधायिकाओं की समयावधि 5 साल के स्थान पर 8,10 साल कर सकते है, पूरे देश में एक झटके में यूनिफार्म सिविल कोड लागू कर सकते है। प्रचंड बहुमत की सरकार ठान ही ले तो आरक्षण खत्म कर सकती है, ओर बहुत सी ऐसी ही बातें हैं जो किसी भी दल की सरकार, अपने शासन को निरन्तरता देने के इरादे से कर सकता है!!

इसी समूह में एक व्यक्ति जो थोड़ा असहज व पृथक सा लग रहा रहा था, उसने दबी आवाज में कहा कि आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान संशोधन की भी क्या जरूरत है? आसान रास्ता है, सरकारों में निम्नतम श्रेणी के पदों पर प्लेसमेंट एजेन्सीज से कॉन्ट्रेक्ट पर कर्मचारी ले लो, उच्च श्रेणी वाले पदों पर बाहर से (लेटरल सिलेक्शन) 2,4,5 साल के लिए भर्ती कर लो जैसे अब भी डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल के पद भरे जा रहे है?? पब्लिक सेक्टर के संस्थानों को बेच दो। यह सब करते ही अधिकतर आरक्षण खत्म।

इसी समूह में यह भी सुनने को मिला कि वैसे भी वर्तमानं सत्ता पक्ष के कई छोटे-बड़े नेता, गाहेबगाहे संविधान में बड़े व युग परिवर्तन करी बदलावों की बात कहते ही रहते है। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि उन्होंने 2047 तक के लिए देश की प्रगति का विजन डॉक्यूमेंट बना लिया है!!50 साल तक राज करेंगे ऐसा भी छुटभैया नेताओं से बयान दिलवाए जाते रहे हैं।

एक बात की सो बात और सो बात की एक बात कि प्रचंड बहुमत की सरकार क्या अच्छा व क्या बुरा नहीं कर सकती? संविधान में बिना कई बदलाव के भी उसे प्राणविहीन/ निष्प्रभावी किया जा सकता है। एक अन्य व्यक्ति नें कहा,देखो, कोई भी सरकार हो, संविधान की मूल अवधारणाओं के विपरीत कुछ नही कर सकती और अगर करे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, उन निर्णयों के आधार पर चेलेंज,ऐसे सरकारी फैसलों को खत्म कराया जा सकता है। किसी ओर ने कहा, क्या भोली भाली बातें कर रहे हो, न्यायपालिका में पर्याप्त संख्या में अपने विचारों या यों कहिए कृत्यों के फेवरेबल न्यायाधीश बैठाओ, प्रलोभन की गाजर लटकाओ और स्वतः सब ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी पीरियड की टॉप ब्यूरोक्रेसी के लिए तो कहा गया था कि उन्हें झुकने के लिए कहा तो रेंगने लग गए किन्तु प्रचंड बहुमत वाली सरकार ठान ले तो लोकतंत्र के सतम्भ कहे जाने वाले सब संस्थानों से शीर्षासन करवा सकती है!!!

6. किसी अन्य समूह में तो ओर भी रोचक बात सुनने को मिली। वहां कइयों का विचार था कि संविधान बदले बिना भी बहुत से काम हैं जो केवल व केवल एक प्रचंड बहुमत वाली और शक्तिशाली नेतृत्व वाली सरकार ही कर सकती है। जैसे इस सरकार नें योग, आयुर्वेद, बाजरे-मक्का-ज्वार-रागी जैसे मोटे अनाजों को को विश्व पटल पर पहचान दिलाई वैसे ही प्रबल इच्छा शक्ति और शक्तिशाली नेता हो तो हमारे पुराने ज्ञान को, जो वेदों-उपनिषदों-अनेकानेक पुराणों में दबा पड़ा है, उसे विश्वपटल पर मान्यता दिला सकती है। हमारे यहां सदियों पहले अंगप्रत्यरोपण, विमान निर्माण, कई दूर तक मार करने वाले हथियारों के निर्माण का ज्ञान-विज्ञान था, उसे विश्व को बताया जाएगा। भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिलवाया जाएगा। यह पाश्चात्य व अरब देशों की साजिश थी कि हमारी भूतकाल की उपलब्धियों की जानकारियों से संसार को महरूम रखा!!

7. किसी ओर समूह के एक व्यक्ति की पीड़ा थी कि हमारे इतिहास का भी पुनर्लेखन होना चाहिये जो केवल 400 पार वाली सरकार ही कर सकती है। पुरानी सरकारों के राज में लिखे इतिहास में बाहरी आक्रमणकारियों का यशोगान किया गया है और हमारे बहादुर राजे-महाराजाओं, जिनकी वीरताओं के आगे ग्रीक, अरब, मुगल-सुगल-अंग्रेज कहीं टिकते ही नही थे, उन को गौण किया गया है या कमतर दिखाया गया। यह एक बड़ी साजिश थी और उसे केवल 400 पार के प्रचंड बहुमत वाली सरकार ही ठीक कर सकती है।

8. किसी अन्य समूह में एक ओर राय सामने आई कि चीन, रूस में सुप्रीम बोस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कई बार कानून बदलते है न, तो भारत में भी क्यों नही हो सकता? अन्य कई देशों में भी एकलवादी शासनाध्यक्ष को गद्दी पर कायम रखने के लिए संविधान बदलते रहते है। अगर यहां भी हो जाए तो आम आदमी को क्या फर्क पड़ना है????

देश का सुप्रीम नेता स्ट्रांग तो होना ही चाहिए जिस से विदेशों में देश क्रा गौरव बढ़े। पाकिस्तान व चीन जैसे देश पड़ोसी उसका नाम सुनते ही थरथर कांपने लगें। मालद्वीप व दूसरे छोटे-छोटे देश देश के हितों के विपरीत कुछ करने की सपने में भी न सोचें। एक साथ वाले नें थोड़ा संसोधन का प्रयास किया-- भाई जी, नेता स्ट्रांग तो हो किन्तु इतना भी नहीं कि बाकी सहयोगी शून्य हो जाएं और वह केवल अपने मन की ही सुने और सुनाए।

9. एक ओर राय किसी सज्जन की सुनाई दी। भारत अनेक पंथों-संप्रदायों-पूजा पद्दतियों, बोलियों व भाषाओं, संस्कृतियों, त्योंहारों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाला देश है। इसे चलने के लिए इन सब को एक साथ लेकर चल सकने वाला, समन्वयकारी नेता चाहिए।

वैसे एक राय यह थी कि चुनाव के समय इस प्रकार के उल्टे-सीधे बयान, चाहे कोई भी दल दे, केवल जनता को भ्रमित करने और वोट लेने के लिए दिए जाते हैं। जिनका आम जनता के दैनिक जीवन और उसकी कठिनाइयों से कोइ खास सम्बन्ध नहीं होता। देश में सामाजिक स्तर पर भाईचारा बना रहे तभी देश मजबूत होगा, प्रगति करेगा।

–महावीर सिंह,
पूर्व आईएएस

प्रधानाध्यापक के स्कूल में शराब पीकर आने से विद्यार्थियों व ग्रामीणों में आक्रोश

प्रधानाध्यापक की यह कोई पहली घटना नहीं है, अपितु पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है

मसूदा, (निसं)। राज्य सरकार एवं राज्य के शिक्षा मंत्री विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के प्रति जागरूकता दर्शाते हुए शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के आए दिन बयान आते रहते हैं। वहीं ब्यावर जिले के मसूदा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्षेत्र के कोट का बाड़िया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के फतहराज नामक शराबी प्रधानाध्यापक द्वारा राज्य सरकार एवं राज्य के शिक्षा मंत्री की बयानबाजी को शायद ठेंगा दिखाने का प्रयास किया जाना प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पहली बार शराब के नशे में विद्यालय आना हुआ हो अपितु पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है।

प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों एवं ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किया।

पुनरावृति का उदाहरण मंगलवार को एक बार फिर उस समय सामने आया जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक फतेहराज शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे। इसको लेकर विद्यार्थियों द्वारा अभिभावकों को की गई शिकायत को लेकर अभिभावक एवं ग्रामवासियों के विद्यालय में पहुंचने पर प्रधानाध्यापक के शराब के नशे में पाए जाने के साथ ही संबंधित प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों एवं ग्रामवासियों के साथ अभद्र व्यवहार तक करने की हिम्मत जुटा ली। यही नहीं अभिभावकों द्वारा शराबी प्रधानाध्यापक से जब यह पूछा कि वे शराब पीकर विद्यालय में आते हैं तो विद्यार्थियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों से ही सवाल करने शुरू कर दिए कि शराब पीकर आना कौन सा गुनाह कर दिया। प्रधानाध्यापक ने अपनी दबंगई दिखाते हुए शराब की बोतल को पीछे रखकर टेबल पर पड़ी बोतल को मुंह से लगाकर कहा ये लो पीऊंगा, क्या करोगे मेरा। इसी दौरान प्रधानाध्यापक ने सबके सामने यह और कहा कि पहले मैंने शराब पी अब बीड़ी भी पीउंगा और यह कहते हुए जेब से बीड़ी का बंडल भी निकाल लिया।

उक्त प्रधानाध्यापक की यह कोई पहली घटना नहीं है अपितु पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं करने पर यहां से झांक विद्यालय में प्रतिनिधित्व पर भेज दिया था परंतु कुछ समय बाद प्रधानाध्यापक ने इसी विद्यालय में पुनः कार्यभार करने के बाद से ही लगातार आए दिन शराब पीकर विद्यालय में आने की घटनाओं की लगातार की जा रही पुनरावृति के क्रम में मंगलवार को एक बार फिर शराब पीकर विद्यालय में आने की घटना को दोहराया गया। घटनाक्रम की जानकारी अभिभावकों व ग्रामवासियों द्वारा नोडल विद्यालय नया गांव के पीईईओ को देने पर नया गांव के पीईईओ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानचार्य नरेन्द्र कुमार शर्मा ने विद्यालय के एक प्राध्यापक बलवीर दान को घटनास्थल कोट का बाडिया विद्यालय भेजा। प्राध्यापक बलवीरदान ने घटना स्थल का मौका पर्चा बनाकर अभिभावकों व ग्रामवासियों के बयान दर्ज किए। उधर ग्रामवासियों व अभिभावकों ने विद्यालय पर तालाबंदी किए जाने की चेतावनी दी है।

मसूदा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवकुमार दुबे से इस मामले में जानकारी चाहने पर उन्होंने अपने को जयपुर होने व घटना के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कल कार्यालय समय में जानकारी लेने को कहा है। इस घटना को लेकर मसूदा क्षेत्र के विधायक के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के मद्देनजर क्षेत्रीय विधायक का भी पक्ष जानने को आवश्यक समझते हुए विधायक वीरेन्द्र सिंह कानावत से दूरभाष पर सम्पर्क करने का प्रयास किया परन्तु उनका फोन नो रिप्लाई आने से सम्पर्क तो नहीं हो सका।

■ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मसूदा का कहना है कि जयपुर आया हुआ हूं, इस घटना की जानकारी नहीं है, कल कार्यालय समय में घटना की जानकारी ली जाएगी

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मसूदा का कहना है कि कार्यालय कार्य से आज जयपुर आया हुआ हूं। इस घटना की जानकारी नहीं है। कल कार्यालय समय में घटना की जानकारी ली जाएगी।

भीषण गर्मी में चिकित्सालय में रोगियों की भरमार

फुलेरा, (निसं)। कस्बे की जोबनेर सड़क स्थित राजकीय उपजिला चिकित्सालय को क्रमौन्नत हुए लगभग एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन आज दिन तक उसे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई जो कि जनता के लिए आवश्यक है।

जानकारी अनुसार उप जिला चिकित्सालय के अनुरूप न तो चिकित्सकों के पद हैं, न ही नर्सिंग स्टाफ के और न ही उतनी जांचें उपलब्ध हैं, जो एक उपजिला चिकित्सालय में होनी आवश्यक है। इस भीषण गर्मी में आउटडोर में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुखार, उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गर्मी के मौसम में डीहाइड्रेशन से ऐसी स्थिति बन रही है। वहीं एक बैड पर ही दो-दो मरीजों को लेटाकर उपचार दिया जा रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए वार्डों में कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मौसम में पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं। वार्डों में अभी तक कूलर तक नहीं लगाए है। साथ ही इंडोर पेशेंट के नाम से चिकित्सालय में कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। फस्ट-एड देकर जयपुर रैफर कर दिया जाता है। ना तो मरीज को भर्ती किया जाता है और ना ही ऑपरेशन किए जाते हैं।

■ फुलेरा के राजकीय उपजिला चिकित्सालय को क्रमौन्नत हुए लगभग एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन आज दिन तक उसे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई जो कि जनता के लिए आवश्यक है

चिकित्सालय का स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सीमित कर रखा है। एक उपजिला चिकित्सालय स्तर के चिकित्सालय में कोई जनरल सर्जन एम.एस नहीं है, न ही ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न ही ईएनटी सर्जन है। दुर्घटना होने पर मरीज को तुरंत रैफर कर दिया जाता है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 1 मई, 2024

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2081, श्रवण नक्षत्र रात्रि 3:11 तक, शुभ योग रात्रि 8:01 तक, बालव करण सांय 4:54 तक, चन्द्रमा मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मेष, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज गुरू कृत्तिक 2 वृष राशि में दिन 1:02 पर प्रवेश करेगा। आज शीतलाष्टमी, बूढ़ा बास्योडा, कालाष्टमी है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:08 तक, शुभ 10:46 से 12:24 तक, चर 3:40 से 5:18 तक, लाभ 5:18 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:52, सूर्यास्त 6:55

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

सिंह
स्वास्थ्य से संबंधित चिन्ता दूर होगी। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कन्या
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

तुला
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यक्तिगत प्रयासों से महत्वपूर्ण कार्यों का क्रियान्वयन होगा।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।